

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या—२०५ / २०१९

दिल मोहन सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, योजना—सह—वित्त विभाग, (वित्त विभाग), झारखण्ड सरकार, राँची।
3. उपायुक्त, देवघर।
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर।
5. महालेखाकार (ए० एवं ई०), झारखण्ड, राँची।
6. मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, देवघर शाखा, देवघर।
7. सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, देवघर शाखा, देवघर।

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

याचिकाकर्ता के लिए : श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : जी०पी०-II के ए०सी०

०३ / १३.०९.२०१९ याचिकाकर्ता और राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्ता डब्ल्यू०पी० (एस०) सं० ३२६१ / २०१७ का पुनःस्थापन चाहता है जिसे निर्धारित समय के भीतर शेष त्रुटियों को दूर करने में विफलता पर दिनांक २६.०९.२०१८ के अनुलंघनीय आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका क्योंकि याचिकाकर्ता उस तारीख को अप्रतिनिधित्व रहा। हालांकि, याचिकाकर्ता रिट याचिका में

सेवानिवृत के बाद के लाभों की मांग कर रहा है और यदि रिट याचिका को पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, तो उसे अपूरणीय रूप से क्षति होगा, जबकि उसकी गलती नहीं है।

राज्य के विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थना का विरोध नहीं करते हैं।

किए गए सबमिशन के मद्देनजर, डब्ल्यूपी० (एस०) सं० 3261 / 2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान् अधिवक्ता द्वारा रिट याचिका में बचे हुए त्रुटियों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। कार्यालय जाँच करे और उसके बाद उपयुक्त शीर्षक के तहत सूचीबद्ध करे।

तदनुसार, यह याचिका निपटाई जाती है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया०)